दैनिक

फाईट अगेंस्ट क्रिमिनल

FAC NEWS

वर्ष : १० | अंक:१२५ | मुंबई, शुक्रवार २५ सितंबर २०२६ | RNI. No. : MAHHIN/2016/71734 | पृष्ठ-४ | मूल्य २/रू.

शराब की हर बोतल पर 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज, खाली बोतलें वापस करने पर रिफंड, तमिलनाडु CM विजय का एक और फैसला

तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टीएएसएमएसी) आउटलेट से शराब खरीदने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। अक्टूबर के पहले सप्ताह से प्रति बोतल 10 रुपये ज्यादा देने पड़ सकते हैं। यह एक प्रस्तावित व्यवस्था के तहत है, जिसमें खाली बोतलें वापस करने पर पैसे वापस (रिफंड) मिलने का प्रावधान है। यह रकम हर बोतल पर छपी ज्यादा से ज्यादा रिटेल कीमत (एमआरपी) के अलावा ली जाएगी। इस कदम से काउंटर पर चुकाई जाने वाली रकम बढ़ जाएगी, लेकिन खाली बोतलें वापस करने पर ग्राहकों को 10 रुपये वापस मिल जाएंगे।

स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में बैन होगा जंक फूड, बिक्री पर लगेगी रोक !

केंद्र सरकार स्कूलों के आसपास जंक फूड पर बड़ा

प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है. नई प्रस्तावित नीति के तहत स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में हाई फैट, शुगर और साल्ट (HFSS) वाले खाद्य पदार्थों, जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स बर्गर, नूडल्स और पैकेज्ड स्नैक्स की बिक्री और विज्ञापनों पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी. इस कदम का खास मकसद बच्चों को कम उम्र में ही ज्यादा नमक, चीनी और वसा वाले खाने से दूर रखना है. ऐसे में प्रस्तावित व्यवस्था का असर स्कूलों के आसपास मौजूद दुकानों और खाने-पीने के स्टॉल पर पड़ सकता है. हालांकि, इन नियमों को लेकर कारोबारियों की तरफ से कमाई पर असर को लेकर चिंता भी जताई गई है.

पनवेल डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त के नवीनीकृत कार्यालय का उद्घाटन माननीय पुलिस आयुक्त श्री मिलिंद भारंबे द्वारा किया गया।

इस अवसर पर माननीय संयुक्त पुलिस आयुक्त श्री दीपक सकोरे, माननीय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री प्रमोद शेवाले, सभी माननीय पुलिस उपायुक्तों के साथ-साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कोलाबा में दीवार से टकराई बाइक... दो सगे भाइयों की मौत!

मुंबई। कोलाबा इलाके में बुधवार तड़के तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर एक इमारत की कंपाउंड वॉल से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार दो सगे भाइयों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 22 वर्षीय सुमित सतवन वाल्मीकि और उसके 15 वर्षीय छोटे भाई संजू सतवन वाल्मीकि के रूप में हुई है। दोनों कफ परेड के गणेश मूर्ति नगर इलाके में रहते थे। उनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के पिपरी गांव का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार, हादसा 23 सितंबर की सुबह करीब 4:45 से 5 बजे के बीच नानाभाई मूसा मार्ग के उत्तर दिशा वाले हिस्से में हुआ। सुमित TVS Raider (MH 01 FK 3556) मोटरसाइकिल चला रहा था, जबकि उसका छोटा भाई संजू पीछे बैठा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गैंगोट्री बिल्डिंग की कंपाउंड वॉल से जा टकराई।

‘ज्ञानेश कुमार हटाओ, SIR रोको’

CJP का 48 घंटे का अल्टीमेटम, देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी

नई दिल्ली। चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर विवाद के बीच अब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चुनाव आयोग से जुड़ी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले करीब 10 महीनों में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मतदाता सूची, नाम जोड़ने-हटाने, बहाली और SIR से जुड़ी प्रक्रियाओं पर करीब 14 बार आपत्तियां दर्ज कराई थीं। हालांकि चुनाव आयोग ने इन मतभेदों को आंतरिक प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए कहा है कि आयोग के फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। इसी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए CJP ने गुरुवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोला। ण्ड्ड संस्थापक अभिजीत दीपके ने उन्हें देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बताते हुए 48 घंटे के भीतर इस्तीफा देने की मांग की। ण्ड्ड ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के मौजूदा कामकाज में यह तय होने लगा है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन हारेगा और किसे मतदान का अधिकार मिलेगा। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ण्ड्ड ने अपनी तीन प्रमुख मांगें सामने रखीं। पहली मांग ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की है। दूसरी मांग आगामी सभी चुनावों पर रोक लगाने की है, जबकि तीसरी मांग एंईं प्रक्रिया को तत्काल बंद करने की है। पार्टी ने यह भी मांग उठाई कि SIR से जुड़ी सभी फाइलों को सुप्रीम कोर्ट अपनी कस्टडी में ले, ताकि रिकॉर्ड सुरक्षित रहें और बाद में दस्तावेजों के नष्ट होने का कोई सवाल न उठे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ण्ड्ड ने दावा किया कि अब तक 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जा चुके हैं। पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वोटों के अंतर का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि क्या बड़े पैमाने पर मतदाता नाम हटाने से चुनावी परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। ण्ड्ड ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में मतदाता सूची में हुए बदलावों का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि इसका असर विपक्षी दलों और उनके नेताओं पर पड़ा है। हालांकि इन

दावों और मतदाता नाम हटाए जाने तथा चुनावी परिणामों के बीच कारणात्मक संबंध की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। पश्चिम बंगाल के मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि SIR के दौरान हटाए गए 27.16 लाख नामों में से 22 लाख से अधिक लोगों ने बहाली के लिए अपील की है। ण्ड्ड ने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी और क्षेत्रीय नेताओं को कमजोर करने के लिए मतदाता सूची में बदलाव का इस्तेमाल किया गया। पार्टी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन समेत कई नेताओं का उल्लेख करते हुए मतदाता नाम हटाए जाने और उनके चुनावी प्रदर्शन के बीच संबंध होने का दावा किया।

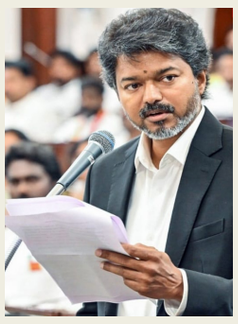

ज्ञानेश कुमार की वजह से जीत रही बीजेपी- CJP

CJP नेता अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय दलों के चुनाव चिह्न और फंड कथित तौर पर बागी गुटों को सौंपे गए और इन्हें बीजेपी की ‘प्रॉक्सी पार्टियां’ बताया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीत रही, बल्कि ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनावी व्यवस्था का फायदा उसे मिल रहा है। ण्ड्ड ने यह भी आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार एक के बाद एक राज्यों में बीजेपी को चुनावी लाभ पहुंचा रहे हैं। इन आरोपों का चुनाव आयोग ने समर्थन नहीं किया है।

‘मोदी के घर पर चपरासी बन जाएं’, CJP

प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP ने ज्ञानेश कुमार पर तीखी व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चापलूसी करना चाहते हैं तो उनके घर पर चपरासी बन जाएं। पार्टी ने ज्ञानेश कुमार को 48 घंटे का समय देते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। ण्ड्ड ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा और दिल्ली में फिर बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। पार्टी ने यह भी कहा कि जब तक चुनावी व्यवस्था में सुधार नहीं होता, तब तक विपक्षी दलों को चुनावों के बहिष्कार पर विचार करना चाहिए।

आखिरी 2 घंटों में 42 लाख वोट कैसे? अरविंद सावंत ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और EVM पर उठाए सवाल

शिवसेना ठाकरे गुट सांसद अरविंद सावंत ने चुनाव आयोग के एसआईआर फैसले, उद्धव ठाकरे की चुनावी मांग, महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति, राहुल गांधी की राजनीतिक भूमिका और आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी।

एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के इस बयान पर कि प्रक्रिया सर्वसम्मति से लिए गए फैसले के बाद शुरू हुई, सावंत ने आयोग पर तीखा हमला बोला और गंभीर आरोप लगाए। अरविंद सावंत ने चुनाव आयोग पर सत्ता पक्ष के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह पहले भी कई बार कह चुके हैं कि आयोग सत्ता का गुलाम है और उनसे निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती। उद्धव ठाकरे ने भी इस मुद्दे को लेकर पत्रकार परिषद में मांग रखी है। चुनाव आयोग के अधिकारियों को जेल जाना चाहिए। उन्होंने चुनाव के दौरान आखिरी दो घंटों में 42 लाख लोगों के मतदान करने के सवाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी पारदर्शिता को लेकर सवाल उठे थे। सावंत ने कहा कि अगर आयोग के पास मतदान केंद्रों पर भीड़ और मतदान की प्रक्रिया से संबंधित सीसीटीवी रिकॉर्ड था तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। उन्होंने चुनाव आयोग पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग को लेकर जनता के मन में लगातार सवाल उठ रहे हैं। अरविंद सावंत ने भाजपा सांसद संबित पात्रा के चुनाव आयोग के समर्थन में उतरने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पात्रा को सत्ता पक्ष का समर्थक बताते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से वकालत करते हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान ईवीएम में आग लगने के मुद्दे का जिक्र करते हुए संबित पात्रा से सवाल किया कि इसकी जांच की मांग क्यों नहीं की गई। अगर मशीन में कथित भ्रष्टाचार पकड़े जाने का डर था तो मशीन को ही जला दिया गया।

दैनिक
फाईट अगेंस्ट क्रिमिनल
मुंबई, शुक्रवार २५ सितंबर २०२६

संपादकीय

एम.एस.शेख
संपादक

यूपीआई तंत्र के हित में है एमडीआर

असली सवाल शुल्क की दर से ज्यादा उसकी वजह का है। यूपीआई पर हर साल करीब ₹20,000 करोड़ रुपये खर्च सिर्फ सर्वर, साइबर सुरक्षा और तकनीकी ढांचे पर आता है।

यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस वह सिस्टम है, जिसकी वजह से हम मोबाइल से तुरंत किसी को भी पैसे भेज या मंगवा सकते हैं। इसे 2016 में एनपीसीआई (नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया) ने शुरू किया था और तब सिर्फ 44 बैंक इससे जुड़े थे। आज 750 से अधिक बैंक इससे जुड़े हैं। शुरुआत में इसका इस्तेमाल बहुत कम था, लेकिन आज हर महीने 2,400 करोड़ से भी ज्यादा लेनदेन इसी के जरिये हो रहे हैं। यानी हर दिन करीब 80 करोड़ से अधिक बार लोग यूपीआई से पैसे भेज या ले रहे हैं। यह बदलाव सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं।

गांव की छोटी दुकान, ठेले वाला, आटो चालक आदि सब यूपीआई क्यूआर कोड से जुड़ चुके हैं। इसने नकदी पर निर्भरता को कम किया है और बैंकिंग को उन लोगों तक पहुंचाया है, जिनके पास पहले कभी डेबिट-क्रेडिट कार्ड नहीं था। इसने छोटे व्यापारियों को बिना किसी भारी उपकरण या शुल्क के डिजिटल भुगतान अपनाने का मौका दिया। अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो यूपीआई ने भुगतान की लागत को शून्य कर दिया, जिससे औपचारिक आर्थिकी का दायरा बढ़ा और वित्तीय समावेशन को नई गति मिली। यही वजह है कि आज यूपीआई सिर्फ एक तकनीकी सुविधा नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल आर्थिकी की रीढ़ है।

यूपीआई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खूब सराहा गया है। आईएमएफ ने जून 2025 में यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रीयल-टाइम भुगतान तंत्र बताया था, जो विश्व का करीब 49 प्रतिशत रीयल-टाइम डिजिटल लेनदेन संभालता है-ब्राजील, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से भी अधिक। आज भूटान, नेपाल, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, श्रीलंका, मारीशस और मालदीव समेत करीब एक दर्जन देश यूपीआई को अपना चुके हैं और कई देश अपने डिजिटल भुगतान ढांचे को इसी माडल पर बनाने पर विचार कर रहे हैं। अब इसी मुफ्त सिस्टम में 15 अक्टूबर, 2026 से मामूली शुल्क लगने जा रहा है, जिसे एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहा जाता है। एनपीसीआई के इस फैसले ने हलचल पैदा की है, लेकिन असली तस्वीर समझने के लिए इसे आंकड़ों और अर्थशास्त्र की नजर से देखना जरूरी है। सबसे पहली बात यह कि 2,000 रुपये तक के यूपीआई भुगतान पूरी तरह मुफ्त ही रहेंगे और यही रकम कुल भुगतान (यानी जब किसी दुकानदार को यूपीआई से पैसे दिए जाते हैं) का 95 प्रतिशत से भी ज्यादा हिस्सा है। मतलब सौ में से 95 से ज्यादा बार जब आप यूपीआई से पैसे देंगे तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। यूपीआई भुगतान पर शुल्क सिर्फ उन पांच प्रतिशत से भी कम लेनदेन पर लगेगा जो 2,000 से अधिक के होंगे और वह भी सिर्फ बड़े दुकानदारों-कारोबारियों पर। जो छोटे दुकानदार महीने में एक लाख रुपये तक यूपीआई क्यूआर कोड से कमाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए सब कुछ पहले जैसा मुफ्त ही रहेगा। दर भी बहुत मामूली रखी गई है-सिर्फ 0.4 प्रतिशत और वह भी 75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर अधिकतम 300 तक।

JANSEVA SOCIAL FOUNDATION
Non Goverment Organization
Reg. No. F-75914

NITI AYOG
12A,80G
& CSR
Registered

DONATE FOR POOR AND UNDERPRIVILEGED

Contact us
9930026943

SBI BANK
JANSEVA SOCIAL FOUNDATION
Account No:.39171751769
IFS Code : SBIN0012959
www.jansevasocialfoundation.com

701/ C Wing crystal Plaza opposite infinity mall Andheri West

ध्ण के बदले 10इ हिस्सेदारी और टेरेस फ्लैट मांगने का आरोप, विधायक नरेंद्र मेहता ने किया खारिज

दामोदर टॉवर के डेवलपर का दावा-विनोद मेहता ने भी की फ्लैट की मांग; दो कथित ऑडियो क्लिप पुलिस को सौंपीं, मंत्री प्रताप सरनाईक की बैठक में सात दिन में ध्ण जारी करने का निर्देश

नजमुल हसन रिज़वी

मीरा भायंदरः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बालमित्र असगर अली वोरा और नया नगर के जमिनी विवाद के बाद भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता एक और बिल्डिंग विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। भायंदर के नवघर बी पी रोड़ पर स्थित दामोदर टॉवर इमारत के भोगवटा प्रमाणपत्र (ध्ण) को लेकर विवाद गहरा गया है। इमारत के डेवलपर देवराम मांडोरा ने भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता पर ध्ण जारी कराने के बदले विकास परियोजना में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी तथा महापौर डिंपल मेहता के पति विनोद मेहता पर टेरेस फ्लैट मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। डेवलपर ने अपनी शिकायत के समर्थन में दो कथित ऑडियो क्लिप पुलिस को सौंपी हैं।

विधायक नरेंद्र मेहता ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज किया है। उनका कहना है कि पुनर्विकसित इमारत के पुराने रहवासियों को घर मिलने तक ध्ण जारी नहीं करने के निर्देश उन्होंने दिए थे। इस बीच, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की अध्यक्षता में गुरुवार को नगररचना विभाग में हुई बैठक में प्रशासन को सात दिनों के भीतर ध्ण जारी करने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, शिकायत और ऑडियो क्लिप की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है।

OC रोकने के पीछे राजनीतिक दबाव का आरोप

नवघर स्थित पुरानी इमारत के पुनर्विकास के बाद दामोदर टॉवर का निर्माण किया गया है। डेवलपर मांडोरा के अनुसार, निर्माण कार्य पूरा होने और आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद उन्हें महानगर पालिका से OC नहीं मिल रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रमाणपत्र जारी करने के बदले उनसे अनुचित मांगें की गईं और ध्ण रोकने के लिए राजनीतिक दबाव बनाया गया।

मांडोरा ने दावा किया कि विधायक नरेंद्र मेहता की ओर से विकास परियोजना में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी, जबकि विनोद मेहता की ओर से एक टेरेस फ्लैट की मांग की गई। इन आरोपों से संबंधित बताई जा रही दो ऑडियो क्लिप पुलिस को सौंपी गई हैं।

हालांकि, ऑडियो की सत्यता और उसमें हुई बातचीत की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

मंत्री की बैठक में सात दिन में ध्ण जारी करने का निर्देश

मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने गुरुवार को नगररचना विभाग में बैठक की। इसमें MBMC आयुक्त राधाबिनोद शर्मा, संबंधित अधिकारी, पुलिस उपायुक्त राहुल चव्हाण और शिकायतकर्ता डेवलपर देवराम मांडोरा उपस्थित थे। बैठक में मांडोरा ने आरोप लगाया कि सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे करने के बावजूद उन्हें भोगवटा प्रमाणपत्र के लिए परेशान किया जा रहा है। इस पर मंत्री सरनाईक ने प्रशासन से जवाब मांगा। सहायक नगररचनाकार पुरुषोत्तम शिंदे ने सात दिनों के भीतर OC जारी करने की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही। मंत्री सरनाईक ने पुलिस उपायुक्त राहुल चव्हाण को शिकायत और ऑडियो क्लिप के आधार पर जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस ने भी ऑडियो की सत्यता की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही।

नरेंद्र मेहता बोले-पुराने रहवासियों को घर दिलाना मकसद

विधायक नरेंद्र मेहता ने डेवलपर के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, 'डेवलपर द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। पुनर्विकसित इमारत के पुराने रहवासियों को डेवलपर घर देने से इनकार कर रहा है। इसलिए मैंने निर्देश दिए थे कि सभी पुराने रहवासियों को उनके घर मिलने तक ध्ण जारी नहीं किया जाए।'

ऑडियो क्लिप को लेकर मेहता ने दावा किया कि यह करीब दो साल पुरानी है और उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संबंधित समय पर वह विधायक नहीं थे। मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा लगाए गए आरोपों को भी निराधार बताते हुए मेहता ने कहा, 'मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं शहर के विकास के लिए काम कर रहा हूं।'

डेवलपर के खिलाफ भी पहले से शिकायतें

इस विवाद में एक अन्य पहलू यह भी है कि डेवलपर देवराम मांडोरा के खिलाफ पूर्व में निर्माण संबंधी कथित अनियमितताओं को लेकर मामला दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। महापौर डिंपल मेहता और विधायक नरेंद्र मेहता की ओर से भी डेवलपर के खिलाफ महानगर पालिका में शिकायत की गई है। फिलहाल, ध्ण जारी करने की समयसीमा, डेवलपर की शिकायत और कथित ऑडियो क्लिप की जांच इस पूरे मामले के अहम पहलू हैं। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

आवारा कुत्तों को खिलाने पर ₹5,000 जुर्माने की वैधता पर सवाल, MBMC से जवाब तलब

पशुपालन विभाग ने सात दिन में मांगी कार्रवाई रिपोर्ट; कानूनी राय लेकर 2023 के नियमों के अनुरूप निर्णय लेने का निर्देश

नजमुल हसन रिज़वी

मीरा भायंदर : मीरा भायंदर महानगर पालिका (MBMC) द्वारा निर्धारित स्थानों के अलावा अन्य जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर ₹5,000 तक का जुर्माना लगाने के फैसले की अब कानूनी समीक्षा होगी। जिला पशुपालन विभाग ने इस जुर्माने की वैधता की जांच करने और सात दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करने का निर्देश महानगर पालिका प्रशासन को दिया है।

महानगर पालिका ने सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से होने वाली गंदगी, दुर्गंध और नागरिकों को हो रही परेशानी की शिकायतों के मद्देनजर शहर में कुछ स्थान निर्धारित किए थे। इन निर्धारित स्थलों के अलावा अन्य जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर ₹5,000 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया था।

हालांकि, महानगर पालिका के इस फैसले का पशु कल्याण कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इसके बाद पशु कल्याण कार्यकर्ता रोशन पाठक ने जिला पशुपालन विभाग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत

के आधार पर विभाग ने 4 सितंबर को महानगर पालिका को पत्र भेजकर जुर्माने की कानूनी वैधता की जांच करने का निर्देश दिया।

विभाग ने MBMC प्रशासन से अपने विधि विभाग की आधिकारिक राय लेने और जुर्माने के प्रावधान को पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 (Animal Birth Control Rules, 2023) तथा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित करने को कहा है।

इस मामले में महानगर पालिका को सात दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपनी होगी। इससे पहल ` प्रशासन स्पष्ट कर चुका है कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और निर्धारित फीडिंग स्पॉट की संख्या बढ़ाई जाएगी। जिला पशुपालन विभाग के अनुसार, जुर्माने की वैधता को लेकर विधि विभाग की राय और संबंधित नियमों के परीक्षण के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब महानगर पालिका के ₹5,000 के जुर्माने पर अंतिम निर्णय कानूनी समीक्षा के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

'इसमें बेइज्जती क्या है?'.. 'बुड्ढी' कहने वालों को करीना का करारा जवाब

बेबो यानी करीना कपूर को उम्र और चेहरे की झुर्रियों पर ट्रोल करना सोशल मीडिया यूजर्स को भारी पड़ गया था। एक बार करीना ने अपनी सहेली अमृता अरोड़ा और दोस्तों के साथ पार्टी की तस्वीर शेयर की। फोटो सामने आते ही कुछ ट्रोलर्स ने उन्हें 'बुड्ढी' कहकर उम्र पर निशाना साधना शुरू कर दिया। लेकिन करीना भी कहां चुप बैठने वाली थीं! बेबो ने ट्रोलर का कमेंट उठाया और ऐसा जवाब दिया कि मामला ही पलट गया। करीना ने सवाल किया कि आखिर किसी महिला को 'बुड्ढी' कहना अपमान क्यों माना जाता है? उन्होंने साफ कहा कि उम्र में बड़ा और समझदार होना कोई शर्म की बात नहीं है। साथ ही ट्रोलर्स से पूछा कि वे खुद बिना नाम, चेहरे और उम्र के छिपकर कमेंट क्यों कर रहे हैं। करीना का यह बेबाक अंदाज सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर ले गया।

अंतिम पलों में भारत ने मारी बाजी, मिक्स्ड 4x400 रिले में जीता सिल्वर

भारतीय मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम ने गुरुवार को 3:14.46 सेकंड का समय लेकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। नागोया सिटी मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में मचेत्तिरा पूवम्मा, विशाल थेन्नारासु, रामराज विथ्या और थेक्किनालिल मनु की भारतीय चौकड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वियतनाम को पीछे छोड़ा।

बहरीन ने 3:12.87 सेकंड के गेम्स-रिकॉर्ड समय के साथ गोल्ड मेडल जीता। वियतनाम (3:14.54 सेकंड) ने तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि जापान 3:15.52 के समय के साथ चौथे स्थान पर रहा।

भारत ने लगातार तीन संस्करणों में जीता मेडल

शुरुआत में वियतनाम पर भारत की 0.08 सेकंड की बढ़त निर्णायक साबित हुई, क्योंकि पोडियम के लिए हुई रोमांचक लड़ाई में भारतीय टीम ने अपना संयम बनाए रखा।

इस नतीजे के साथ एशियन गेम्स में मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में भारत का शानदार रिकॉर्ड जारी रहा। जकार्ता 2018 में गोल्ड और हांग्जो 2023 में सिल्वर मेडल जीतने के बाद, भारत ने अब लगातार तीन संस्करणों में इस इवेंट में मेडल जीता है।

विशाल टीके ने बनाया रिकॉर्ड

तमिलनाडु के स्प्रिंटर विशाल टीके ने पुरुषों की

400 मीटर दौड़ में 45 सेकंड से कम समय लेने वाले पहले भारतीय एथलीट बनकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने रांची में 2026 नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 44.98 सेकंड का समय लिया था।

विशाल ने इससे पहले गुमी (साउथ कोरिया) में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में गोल्ड और पुरुषों की 4400 मीटर रिले में सिल्वर मेडल जीता था। इसके साथ ही वे व्यक्तिगत 400 मीटर दौड़ में चौथे स्थान पर रहे थे।

विधान परिषद की पांच सीटों पर चुनावी बिगुल

मविआ में सन्नाटा, महायुति में दावेदारी की रस्सीखेच

विशेष संवाददाता/ सुनिल इंगोले

मुंबई। विधान परिषद की तीन स्नातक और दो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की पांच सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित हो गया है। 23 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 27 अक्टूबर को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। इन चुनावों में स्थानीय राजनीतिक समीकरण, नेताओं की व्यक्तिगत पकड़, मतदाता पंजीकरण और शिक्षक-स्नातक संगठनों की भूमिका अहम रहने वाली है। पिछले चुनावों में इन सीटों पर महाविकास आघाड़ी ने प्रभाव दिखाया था। हालांकि, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस में विभाजन के बाद राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। महायुति के तीनों घटकों–भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट) और शिवसेना (शिंदे गुट)–में टिकट को लेकर दावेदारी तेज है। वहीं महाविकास आघाड़ी में भी कुछ सीटों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है।

नागपुर स्नातक सीट पर भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने

नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों को शामिल करने वाला नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र भाजपा का पारंपरिक मजबूत क्षेत्र माना जाता रहा है। हालांकि 2020 में कांग्रेस के अभिजीत वंजारी ने भाजपा के तत्कालीन नागपुर महापौर संदीप जोशी को हराकर भाजपा को बड़ा झटका दिया था। अब भाजपा इस सीट को फिर से हासिल करने की तैयारी में जुटी है। पार्टी ने पूर्व विधायक सुधाकर कोहळे को मतदाता पंजीकरण की जिम्मेदारी दी है। उनके संभावित उम्मीदवार होने की चर्चा है। पूर्व विधायक अनिल सोले के नाम की भी चर्चा है। इसके अलावा सुधीर दिवे, विजय राऊत, किशोर रेवतकर और गिरीश देशमुख के नाम भी सामने आ रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण के विदर्भ दौरे के बाद भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर तैयारियां तेज की हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के मौजूदा विधायक अभिजीत वंजारी ने भी मतदाता पंजीकरण अभियान तेज कर दिया है। ऐसे में नागपुर स्नातक सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना के साथ शिक्षक भारती के अतुल देशमुख की उम्मीदवारी ने मुकाबले को बहुकोणीय बना दिया है।

पुणे स्नातक सीट पर महायुति में टिकट को लेकर खींचतान : पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पुणे के साथ सातारा, सांगली, सोलापुर और कोल्हापुर जिले शामिल हैं। 2020 में महाविकास आघाड़ी के समर्थन से राष्ट्रवादी कांग्रेस के अरुण लाड विजयी हुए थे। इस बार भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट) और शिवसेना (शिंदे गुट) तीनों ही इस सीट पर दावा कर रहे हैं। भाजपा की ओर से शरद लाड का नाम प्रमुखता से चर्चा में है। शरद लाड मौजूदा विधायक अरुण लाड के बेटे हैं और हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा नेता चंद्रकांत पाटील ने पुणे स्नातक और शिक्षक सीट पर भाजपा के दावे की बात कही है। दूसरी ओर अजित पवार गुट भी सीट छोड़ने के पक्ष में नहीं है। भैया माने को लेकर भी पार्टी की ओर से तैयारी की जा रही है। मंत्री हसन मुश्रीफ ने मतदाता पंजीकरण को लेकर बड़ा दावा किया है। शिवसेना (शिंदे गुट) की ओर से शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी श्वेता देशमुख के नाम की भी चर्चा है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ने बालासाहेब थोरात को समन्वयक नियुक्त किया है, लेकिन सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) को मिलने की संभावना को लेकर कांग्रेस के भीतर असंतोष की चर्चा है।

छत्रपति संभाजीनगर में सतीश चव्हाण के सामने भाजपा की तैयारी : छत्रपति संभाजीनगर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में आठ जिले–छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी और हिंगोली–शामिल हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट) के मौजूदा विधायक सतीश चव्हाण लगातार तीसरी बार जीत चुके हैं। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी भी घोषित कर दी है और चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी ओर भाजपा में पूर्व विधायक संजय केणेकर को मतदाता पंजीकरण की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा की ओर से उन्हें संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। प्रवीण गुगे का नाम भी चर्चा में है। दोनों शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) की ओर से भी संभावित उम्मीदवारों की तलाश शुरू होने की बात सामने आ रही है।

पुणे शिक्षक सीट पर कई दावेदार

पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पुणे, सातारा, सांगली, सोलापुर और कोल्हापुर जिले शामिल हैं। इस सीट पर लगभग 53,800 शिक्षक मतदाता हैं। कांग्रेस के मौजूदा विधायक जयंत आसगांवकर फिर मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। वहीं बिना अनुदानित स्कूलों के अनुदान के लिए आंदोलन करने वाले खंडेराव जगदाळे भी कांग्रेस से टिकट के इच्छुक बताए जा रहे हैं। भाजपा की ओर से कौस्तुभ गावडे, नंदकुमार सागर और डॉ. पी. बी. रोंगे के नाम चर्चा में हैं। सांसद धनंजय महाडीक द्वारा कौस्तुभ गावडे के लिए प्रयास किए जाने की चर्चा है। वहीं शिवसेना से जुड़े रहे मंगेश चिवटे ने भी शिक्षक मतदाताओं के बीच संपर्क बढ़ाया है। पूर्व विधायक दत्तात्रय सावंत ने भी चुनाव लड़ने के विकल्प खुले रखे हैं। चूंकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव सीधे राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर नहीं होता, इसलिए पार्टी समर्थन के साथ शिक्षक संगठनों की भूमिका और उम्मीदवारों का व्यक्तिगत संपर्क भी महत्वपूर्ण रहने वाला है।

पांचों सीटों पर बदले समीकरण

विधान परिषद की इन पांच सीटों के चुनाव में महायुति के घटक दलों के बीच टिकट को लेकर दावेदारी सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू बनकर सामने आई है। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी की रणनीति भी महायुति द्वारा उम्मीदवार तय किए जाने के बाद और स्पष्ट होने की संभावना है। इन चुनावों में पारंपरिक पार्टी समीकरणों के साथ मतदाता पंजीकरण, स्थानीय संगठन, शिक्षक एवं स्नातक संगठनों का समर्थन और उम्मीदवारों का व्यक्तिगत जनसंपर्क अहम भूमिका निभा सकता है। ऐसे में 23 अक्टूबर के मतदान से पहले इन पांचों निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है।

अमरावती शिक्षक सीट पर सरनाईक बनाम देशपांडे की तैयारी

अमरावती विभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौजूदा विधायक किरण सरनाईक ने शिवसेना (शिंदे गुट) से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पूर्व विधायक श्रीकांत देशपांडे ने भी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि उन्हें शिवसेना से उम्मीदवारी नहीं मिलती है तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। भाजपा की ओर से शेखर भोयर, संगीता शिंदे बोंडे और प्राध्यापक सुमित पवार के नाम चर्चा में हैं। कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री हर्षवर्धन देशमुख की बेटी आदिती पोहरे के नाम की चर्चा है। 2020 के चुनाव के दौरान 'पैठणी पैटर्न' को लेकर आरोप-प्रत्यारोप हुए थे। विपक्ष ने किरण सरनाईक पर शिक्षकों को पैठणी, बैग और पैसे बांटने के आरोप लगाए थे। हालांकि इन आरोपों को आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इस बार चुनाव में किस तरह की रणनीति अपनाई जाती है, इस पर सभी की नजर रहेगी।

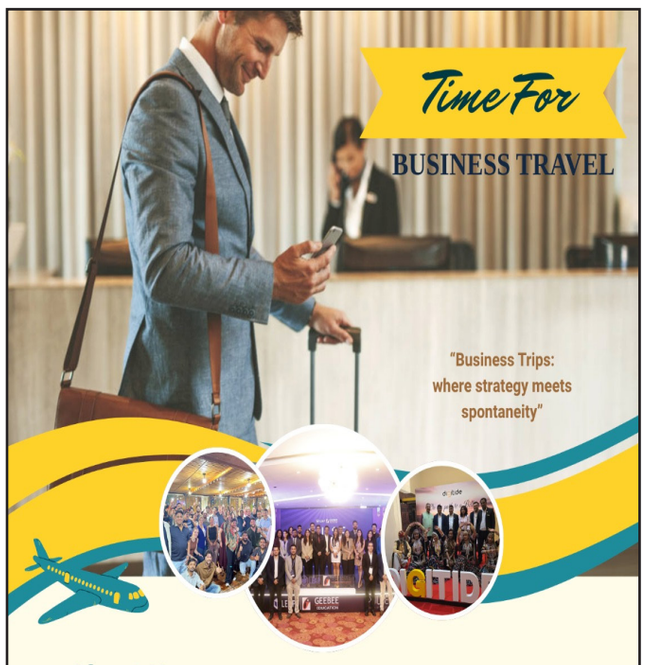

8.46 करोड़ की कारोबारी धोखाधड़ी, कंपनी संचालकों पर केस... 2.50 करोड़ के चेक दिए; 9 बाउंस, 4.5 करोड़ चुकाने का लिखित वादा भी बेअसर

भिवंडी : नारपोली थाना क्षेत्र में कारोबारी लेनदेन के नाम पर करीब 8.46 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कच्चा माल खरीदने के लिए पूंजी की जरूरत बताकर कारोबार में शामिल होने और बाद में माल की रकम का भुगतान नहीं करने का आरोप है। शिकायत के आधार पर नारपोली पुलिस ने APRAN Enterprises Pvt. Ltd. और उसके तीन संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता गौरव अनिल सिंघल (41) की आरोपियों से अगस्त 2024 में पहचान हुई थी। शिकायत में बताया गया है कि आरोपियों की कंपनी को कच्चा माल खरीदने के लिए पूंजी की जरूरत थी। इसके बाद शिकायतकर्ता की कंपनी ने कच्चा माल खरीदकर APRAN Enterprises Pvt. Ltd. और उसकी सहयोगी कंपनियों को बेचने का कारोबारी समझौता किया।

भायंदर के डोंगरी चेकपोस्ट पर नाकाबंदी में दो देसी पिस्तौल के साथ एस्टेट एजेंट गिरफ्तार

उत्तन सागरी पुलिस की कार्रवाई; Kia Sonet समेत ₹20.50 लाख का माल जब्त, हथियारों के स्रोत की जांच जारी

नजमुल हसन रिज़वी

मीरा भायंदरः उत्तन सागरी पुलिस ने डोंगरी कोस्टल चेकपोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान एक Kia Sonet कार से दो देसी पिस्तौल मैगजीन सहित बरामद कर 36 वर्षीय एस्टेट एजेंट को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हथियारों और कार समेत कुल ₹20.50 लाख का माल जब्त किया है।

पुलिस के अनुसार, 23 सितंबर 2026 को तड़के करीब 4.30 बजे डोंगरी कोस्टल चेकपोस्ट पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक ग्रे रंग की Kia Sonet कार (MH-02-MN-3125), वर्ष 2021 मॉडल की तलाशी लेने पर उसमें दो देसी पिस्तौल मैगजीन सहित मिलीं।

कार में सवार आरोपी की पहचान संजय सुरेंद्र सिंह (36) के रूप में हुई है। वह पेशे से एस्टेट एजेंट है और मुंबई के दहिसर पूर्व का निवासी है। मूल रूप से वह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रहने वाला है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। **20.50 लाख का माल जब्त**

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 25,000 मूल्य की प्रत्येक, ऐसी दो देसी पिस्तौल, मैगजीन सहित, और 20 लाख मूल्य की Kia Sonet कार जब्त की है। जब्त किए गए माल का कुल मूल्य ₹20,50,000 बताया गया है।

आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज

इस मामले में उत्तन सागरी पुलिस थाने में भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3 और 25(1)(अ) तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1) सहपठित 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस उपनिरीक्षक कमलाकर चासकर मामले की आगे जांच कर रहे हैं। पुलिस अब बरामद हथियारों के स्रोत, उन्हें अपने पास रखने के उद्देश्य और उनके संभावित इस्तेमाल की जांच कर रही है। साथ ही, इस मामले में अन्य संभावित पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।

स्थानीयों की जमीन पर विमानतल, अब रोजगार में भी मिले पहला हक!

अमरावती। बेलोरा (हिरापूर) स्थित अमरावती विमानतल में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि बेलोरा (हिरापूर) ग्राम पंचायत की सीमा में स्थित अमरावती विमानतल के लिए बेलोरा, हिरापूर और अडगांव खुर्द के स्थानीय रहवासियों की खेती एवं रोजगार का आधार रही जमीन परियोजना में गई है। बेलोरा ग्राम पंचायत ने इस उम्मीद के साथ विमानतल के लिए आवश्यक सभी एनओसी दी थीं कि क्षेत्र के सैकड़ों शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा और उनका जीवनस्तर सुधरेगा। ज्ञापन में कहा गया कि विमानतल में ऑफिस बॉय, क्लीनर और चौकीदार जैसे पदों पर नियुक्तियां निकलने के बावजूद स्थानीय युवाओं को अवसर देने के बजाय दलालों के माध्यम से कथित रूप से 50 हजार रुपये लेकर भर्ती किए जाने की प्रक्रिया शुरू है। ज्ञापन में मांग की गई कि नियमानुसार विमानतल प्रशासन और संबंधित कंपनी को पहले स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देनी चाहिए और उसके बाद अन्य लोगों पर विचार किया जाना चाहिए। आजाद समाज पार्टी की ओर से कहा गया कि बेलोरा गांव की लगभग 70 से 80 प्रतिशत आबादी बेरोजगार है। गांव के आसपास कोई औद्योगिक क्षेत्र या एमआईडीसी नहीं होने के कारण गरीब परिवारों के लोगों को रोजगार के लिए पुणे, मुंबई जैसे शहरों में जाकर मजदूरी करनी पड़ती है। ज्ञापन में कहा गया कि बेलोरा में विमानतल और एयर इंडिया ट्रेनिंग अकादमी शुरू होने से स्थानीय मजदूरों एवं बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर पैदा हुआ है। लेकिन ट्रेनिंग अकादमी में बाहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मजदूरों की भर्ती किए जाने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा या नहीं, इसे लेकर सवाल खड़ा हो गया है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि बेलोरा गांव के स्थानीय मजदूरों, युवाओं और उनके परिवारों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए रोजगार में उन्हें सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाए। साथ ही स्थानीय लोगों को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराया जाए। मांग पूरी नहीं होने पर 15 दिनों के भीतर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। इस अवसर पर आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रवीण सु. मोहोड, जिला महासचिव विक्रम रा. तसरे, गौतम सवाई, नितीन काळे, अंकुश आठवले, विजय मोहोड, चंदू मोहोड, सिता ओगले, माया सवाई, अर्चना धवणे, शालु सवाई, सुवर्णा वरघट, सारीका सवाई, शालु गोले, रजनी सवाई, सुशिला घुगरे, सुजाता पाटील, बबीता आठवले, अरुणा गोले, दर्षना दाभाडे, साधना।अघम, शिला भारसाकडे,।ललीता ओगले, भुमीका।सवाई, प्रियंका तसरे, माधुरी सवाई और अनिता सवाई उपस्थित थे।

बेलोरा हिरापूर में उन्नति ग्राम संघ की आमसभा, 50 महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण

विशाल गवई

लोणी। बेलोरा हिरापूर में उन्नति ग्राम संघ की आमसभा संध्या दुर्योधन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सदन किसान समूह, बेलोरा हिरापूर की ओर से ग्राम संघ को नियोजन दिए जाने के बाद ग्राम संघ के माध्यम से 50 महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में गांव की आशा कार्यकर्ताओं के साथ पीएचसी की स्वास्थ्य टीम उपस्थित रही। कार्यक्रम की शुरुआत क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले के चित्र का पूजन कर की गई। इस अवसर पर गांव की प्रशासक माधुरी चौधरी, ग्राम पंचायत सदस्य प्रीति आठवले, सचिव कांडलकर मैडम, पूर्व पंचायत समिति सदस्य सविता सवाई, GVCD की BOD सदस्य रेखा वानखड़े तथा ग्राम संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे। संचालक मधुमती खडसे ने स्वागत एवं पूजन कार्यक्रम का संचालन किया। सभा में पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों तथा वर्तमान बैठक

में चर्चा के लिए रखे गए विषयों का वाचन लिपिका ने किया और सभा का प्रस्तावना भाषण भी प्रस्तुत किया। इस दौरान महिलाओं के ग्राम संघ की बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहने के कारणों पर चर्चा की गई।

ग्राम संघ से जुड़े 16 समूहों द्वारा लिए गए सामूहिक निर्णयों तथा दो समूहों द्वारा लिए गए निर्णयों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। समूह की बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों को ऋण दिया जाए या नहीं, इस विषय पर सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों पर चर्चा की गई।

बैठक में उपस्थित ठोंबरे सर ने महिलाओं को विभिन्न समितियों के महत्व और उनकी जिम्मेदारियों की जानकारी दी। साथ ही ग्राम संघ से लिए गए CIF और VRF ऋण की समय पर ग्राम संघ में वापसी तथा चुकाए गए CIF की राशि प्रभाग संघ को वापस करने की प्रक्रिया समझाई गई। महिलाओं को PG समूह गठित कर समान प्रकार का व्यवसाय करने वाली महिलाओं को एक साथ लाकर उद्योग शुरू करने, जिला उद्योग केंद्र तथा PMFME जैसी योजनाओं का लाभ लेकर व्यवसाय को बढ़ाने की जानकारी दी गई। इसके अलावा समूह खेती का उद्देश्य, कम लागत में अधिक उत्पादन, नई तकनीक के प्रति जागरूकता, SOP का क्रियान्वयन तथा इसके लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों के बारे में भी जानकारी दी गई। बैठक के प्रस्ताव पर बैंक जोड़नी समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। साथ ही ग्राम संघ की विभिन्न समितियों की जिम्मेदारियां संबंधित महिलाएं सावधानीपूर्वक और जिम्मेदारी से निभा पाएंगी या नहीं, इस विषय पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर आजीविका सखी किरण लोहकरे तथा कृषि सखी वर्षा सोळंके सहित ग्राम संघ की पदाधिकारी एवं सदस्य महिलाएं उपस्थित रहीं।

नाबालिगों को पुलिस वाहन के बोनट से बांधकर निकाली 'बारात'

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मानसिंग पाटील समेत 17 पुलिसकर्मियों पर केस

मानवाधिकार आयोग की जांच के बाद कार्रवाई; नाबालिगों के साथ कथित क्रूर व्यवहार और अवैध हिरासत का गंभीर मामला

मुन्ना मुजावर

पुणे : हत्या के मामले में हिरासत में लिए गए नाबालिग बच्चों को पुलिस वाहन के बोनट से रस्सी के जरिए बांधकर सार्वजनिक रूप से ले जाने के कथित मामले ने पुणे में खलबली मचा दी है। इस गंभीर मामले में महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा की गई

जांच के बाद अब भारती विद्यापीठ पुलिस थाने में 17 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

इस मामले में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मानसिंग पाटील, सहायक पुलिस निरीक्षक गणेश मोहिते, सहायक पुलिस निरीक्षक स्नेहल थोरात, पुलिस उपनिरीक्षक निलेश राजेंद्र माकाशी, पुलिस हवलदार सुनील हनवटे, पुलिस हवलदार दिनेश टापके, पुलिस कर्मचारी मितेश चोरमोले, सागर चंद्रकांत बोरगे, सोहम कैलास शेंडकर, मंगेश पवार और महिला पुलिस कर्मचारी सुवर्णा दत्तात्रय भिसे समेत अन्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम एफआईआर में दर्ज किए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, 21 जुलाई को कात्रज तालाब के पास एक 17 वर्षीय युवक की हत्या हुई थी। इस हत्या के मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कुछ नाबालिगों को हिरासत में लिया था। आरोप है कि इनमें से तीन नाबालिगों को रस्सी से पुलिस वाहन के बोनट से बांध दिया गया और उन्हें आंबेगांव पठार पुलिस चौकी से भारती विद्यापीठ पुलिस थाने तक ले जाया गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सामने आया और पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठने लगे। नाबालिग बच्चों के साथ कथित तौर पर इस तरह का व्यवहार किए जाने से मामला काफी चर्चा में आया।

इसके बाद महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस

मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच समिति गठित की। जांच समिति की रिपोर्ट में कथित तौर पर आठ नाबालिग बच्चों को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखने, उनके साथ क्रूर व्यवहार करने तथा निर्धारित समय के भीतर उन्हें बाल न्याय बोर्ड के समक्ष पेश नहीं करने जैसी गंभीर बातों का उल्लेख किया गया।

जांच रिपोर्ट में नाबालिगों के अधिकारों और उनके साथ की जाने वाली कानूनी प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए। मानवाधिकार आयोग ने तथ्य-जांच समिति की रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेजों के आधार पर मामले की आगे जांच करने के निर्देश दिए थे। मानवाधिकार आयोग के निर्देश और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अब इस मामले में 17 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मानसिंग पाटील समेत अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम दर्ज होने से पुलिस विभाग में भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। नाबालिग बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर कानून में विशेष प्रावधान मौजूद हैं। ऐसे में पुलिस हिरासत में लिए गए नाबालिगों के साथ कथित तौर पर इस तरह का व्यवहार किए जाने के आरोप ने मामले की गंभीरता और बढ़ा दी है। अब पुलिस जांच में यह स्पष्ट होगा कि घटना के समय वास्तव में क्या हुआ था, नाबालिगों को किस परिस्थिति में पुलिस वाहन के बोनट से बांधा गया, इसमें किस-किस की भूमिका थी और इस पूरी कार्रवाई की जिम्मेदारी किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की थी। मानवाधिकार आयोग की जांच के बाद 17 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज होने से पुणे के इस चर्चित प्रकरण में नया मोड़ आया है। आगे की जांच में सामने आने वाले तथ्यों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

पिंपरी में 'मेड इन पाकिस्तान' ब्यूटी क्रीम की बिक्री का खुलासा; 'एटीबी' की ताबड़तोड़ कार्रवाई!

मुन्ना मुजावर

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड़ शहर में कॉस्मेटिक्स की दुकान से 'मेड इन पाकिस्तान' लिखी नकली ब्यूटी क्रीम बेचने का मामला सामने आया है। पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस के एंटी-टेररिज्म ब्यूरो (एटीबी) ने कार्रवाई करते हुए

पिंपरी के रिवर रोड स्थित एक कॉस्मेटिक्स दुकान पर छापेमारी की और संदिग्ध ब्यूटी क्रीम का स्टॉक जब्त किया। पुलिस के अनुसार, पिंपरी मार्केट क्षेत्र में कारोबार करने वाले एक व्यवसायी द्वारा अपनी दुकान में ऐसी ब्यूटी क्रीम बिक्री के लिए रखी गई थी, जिसके पैकेट पर 'मेड इन पाकिस्तान' लिखा हुआ था। आरोप है कि इन क्रीम को असली कंपनी का उत्पाद बताकर ग्राहकों को बेचने की तैयारी की जा रही थी। जांच के दौरान पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि संबंधित क्रीम भारत में बिक्री के लिए प्रतिबंधित है। इसके बावजूद इसे कॉस्मेटिक्स दुकान में बिक्री के उद्देश्य से रखा गया था। सूचना मिलने के बाद ATB की टीम ने दुकान पर कार्रवाई करते हुए वहां मौजूद क्रीम का स्टॉक अपने कब्जे में लिया। इस मामले में संबंधित व्यवसायी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह प्रतिबंधित और कथित तौर पर नकली क्रीम दुकान तक कैसे पहुंची, इसके पीछे सप्लाई नेटवर्क कौन है और क्या इससे पहले भी बड़ी मात्रा में इस उत्पाद की बिक्री की गई है। पुलिस द्वारा जब्त किए गए माल की भी जांच की जा रही है। जांच में क्रीम की वास्तविकता, उसकी गुणवत्ता, निर्माण एवं आपूर्ति से संबंधित जानकारी सामने आने की संभावना है। इस कार्रवाई के बाद कॉस्मेटिक्स कारोबार में नकली और प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे उत्पाद सीधे तौर पर ग्राहकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े होने के कारण पुलिस इस मामले को गंभीरता से जांच रही है। फिलहाल पिंपरी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच आगे बढ़ने के साथ इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आने की संभावना है।

200 किमी तक 350 सीसीटीवी खंगाले, गुजरात तक पीछा कर दबोचे तीन शातिर

अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, अमरावती में ज्वेलर्स और घरों को बनाया था निशाना; 16.15 लाख का माल बरामद

अमरावती। शहर में ज्वेलर्स की दुकानों और घरों में सेंधमारी कर सोना-चांदी चोरी करने वाले

अंतरराज्यीय गिरोह का अमरावती क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने करीब 200 किलोमीटर के दायरे में 350 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की गतिविधियों का पीछा किया और आखिरकार तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से करीब 16 लाख 15 हजार रुपये का चोरी का माल, बाइक और सेंधमारी में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए गए हैं। मामले की शुरुआत 11 सितंबर 2026 को गाडगेनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज ज्वेलर्स की दुकान में सेंधमारी के मामले से हुई। अज्ञात आरोपियों ने दुकान का शटर तोड़कर सोना-चांदी चोरी किया था। इस मामले में अपराध क्रमांक 978/2026 के तहत बीएनएस की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। जांच आगे बढ़ने पर फेजरपुरा और राजापेठ थाना क्षेत्रों में भी इसी तरीके से चोरी की वारदातें सामने आईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त राकेश ओला के मार्गदर्शन में डीसीपी यशवंत सोलंके, डीसीपी श्याम घुगे तथा डीसीपी क्राइम प्रांजली सोनवणे के आदेश पर क्राइम ब्रांच यूनिट-2 के पीआई अतुल वरने और पीआई दिनेश दहातोंडे के नेतृत्व में दो टीमें गठित की गईं। टीमों ने आरोपियों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए करीब 200 किलोमीटर तक 350 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की। जांच के दौरान 23 सितंबर को पुलिस को पुख्ता सूचना मिली कि आरोपी गणेश मानवतकर अपने दो साथियों के साथ हीरो स्प्लेंडर बाइक क्रमांक एम-28 ... 4711 से चोरी के माल और सेंधमारी के औजार लेकर अकोला से नागपुर की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने राममेघे कॉलेज के पास जंगल में दो स्थानों पर घेराबंदी कर जाल बिछाया। कुछ ही देर बाद एक बाइक पर सवार तीन संदिग्ध दिखाई दिए। तीनों की पीठ पर काले रंग के बैग थे। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया। बैगों की तलाशी लेने पर सेंधमारी में इस्तेमाल होने वाले औजार और चोरी का माल बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने अमरावती के अलावा अकोला के खदान और सिविल लाइन पुलिस स्टेशन क्षेत्र में भी चार चोरी की वारदातों में शामिल होने की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ लातूर, बुलढाणा, वाशिम और अकोला जिलों में पहले से ही 15 से अधिक गंभीर अपराध दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के पास से 4 किलो चांदी, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपये, 10 ग्राम सोने की लगड़ कीमत करीब 1.40 लाख रुपये, 25 ग्राम सोने का बेसर करीब 3.75 लाख रुपये, 60 हजार रुपये कीमत की हीरो स्प्लेंडर बाइक और 10 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं। इसके अलावा कटर, टामी, कैंची, पेचकस, विग और टॉर्च समेत सेंधमारी में इस्तेमाल होने वाले औजार भी जब्त किए गए हैं। जब्त माल की कुल कीमत करीब 16 लाख 15 हजार रुपये बताई गई है। यह कार्रवाई एपीआई महेश इंगोले, पीएसआई गजानन ठोसर, मंगेश परिमल, सचिन बहाले, जहीर शेख, नईम बेग, अतुल संभे, विकास गुडधे, विशाल वाकपांजर, योगेश पवार, राजीक रायलीवाले, चेतन गुल्हाणे, चालक संदीप खंडारे और राहुल दुधे की टीम ने की।

अमरावती में इन चार जगहों पर की थी चोरी

गाडगेनगर थाना – अपराध क्रमांक 978/2026,
फ्रेजरपुरा थाना – अपराध क्रमांक 808/2026,
फ्रेजरपुरा थाना – अपराध क्रमांक 822/2026 ,
राजापेठ थाना – अपराध क्रमांक 790/2026

बेलोरा एयरपोर्ट पर CM फडणवीस के स्वागत से पहले बवाल, प्रोटोकॉल को लेकर पुलिस से भिड़े भाजपा पदाधिकारी

अमरावती। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अमरावती आगमन से पहले गुरुवार सुबह बेलोरा एयरपोर्ट पर प्रवेश को लेकर भाजपा पदाधिकारियों और पुलिस के बीच विवाद हो गया। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं मिलने पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी, नितिन गुडधे सहित कई पदाधिकारियों ने ऐतराज जताया। इसी दौरान एसपी निकेतन कदम और भाजपा पदाधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का विमान मुंबई से बेलोरा एयरपोर्ट पहुंचा था। यहां से उन्हें पश्चिम विदर्भ में सूखे और खरीफ फसलों की स्थिति का जायजा लेने वाशिम जिले के दौरे पर रवाना होना था। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए विधायक रवि राणा, विधायक प्रवीण तायडे और विधायक राजेश वानखड़े सहित कई नेता भी एयरपोर्ट पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी, नितिन गुडधे सहित कई स्थानीय पदाधिकारी एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और निर्धारित प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद पदाधिकारियों और पुलिस के बीच बहस शुरू हो गई। मामला बढ़ने पर एसपी निकेतन कदम भी मौके पर पहुंचे। प्रवेश को लेकर पदाधिकारियों और एसपी कदम के बीच काफी देर तक तीखी बातचीत और नोकझोंक होती रही। वहीं पुलिस की ओर से बताया गया कि मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और वीआईपी प्रोटोकॉल लागू था। निर्धारित सूची के आधार पर ही लोगों को एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जा रही थी। विवाद बढ़ने के बाद कुछ पदाधिकारियों को अंदर जाने की अनुमति दिए जाने की जानकारी सामने आई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पश्चिम विदर्भ में सूखे के हालात और खरीफ फसलों की स्थिति का जायजा लेने वाशिम जिले के दौरे पर पहुंचे। दौरे के दौरान कुछ स्थानों पर किसानों ने फसल नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री के काफिले के सामने नारेबाजी भी की। किसानों की चिंताओं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने पात्र किसानों को राहत और कर्जमाफी देने की बात कही तथा किसानों से चिंता न करने का आह्वान किया। बेलोरा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री के स्वागत से ठीक पहले हुआ यह विवाद अब चर्चा का विषय बन गया है। एयरपोर्ट गेट पर हुई नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

'नियम हैं तो सभी के लिए समान हों'

भाजपा पदाधिकारियों ने पुलिस की कार्रवाई पर ऐतराज जताते हुए कहा कि यदि एयरपोर्ट में प्रवेश के लिए सुरक्षा नियम और प्रोटोकॉल तय हैं, तो उनका पालन सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए। उनका कहना था कि विधायकों के साथ उनके फैंटरों और समर्थकों को अंदर जाने दिया जा रहा है, जबकि पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को प्रवेश द्वार पर ही रोका जा रहा है। पदाधिकारियों ने सवाल उठाया कि जब नियम हैं तो वे सभी के लिए समान क्यों नहीं हैं।

तेज रफ्तार अनुबंधित बस ने चाय विक्रेता को रौंदा...मौके पर मौत...चालक बस छोड़कर फरार

प्रयागराजः यमुनानगर जोन के औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत मिर्जापुर मार्ग पर बेलगाम रफ्तार ने गुरुवार को एक और परिवार की खुशियां छीन लीं। पिपरांव ग्राम मोड़ के पास जनहित हॉस्पिटल के सामने तेज रफ्तार अनुबंधित बस ने 48 वर्षीय चाय विक्रेता रामनारायण गुप्ता को जोरदार टक्कर मार दी। रफ्तार इस कदर तेज थी की रामनारायण का शरीर बस में फंसकर काफी दूर तक घसीटता चला गया था। सुबह तड़के हुए इस हादसे में गंभीर रूप से घायल रामनारायण को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद चालक बस को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। बस रोडवेज से अनुबंधित बताई जा रही है। रामनारायण गुप्ता मूलतः यमुनानगर मेजा क्षेत्र के रहने वाले थे। वर्तमान में परिवार के साथ रामपुर करछना क्षेत्र में रहते थे। वहीं चाय-पान की दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। परिजन के मुताबिक बुधवार को वह मुंबई से लौटे थे। गुरुवार को दुकान खोलने जाते समय वह पिपरांव मोड़ के पास मिर्जापुर मार्ग पर जनहित अस्पताल पहुंचे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। सुबह-सुबह हुए इस हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोग उनको अस्पताल लेकर दौड़े लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। सूचना पर औद्योगिक क्षेत्र थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और बस को कब्जे में ले लिया। चालक के फरार होने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस दुर्घटना के कारणों के साथ बस की रफ्तार, चालक की भूमिका और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

यह दैनिक मालक, मुद्रक, प्रकाशक - मोहम्मद सईद अकबर अली शेख द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, युनिट नं. 4- ग्राऊंड फ्लोर, एन के. इंडस्ट्रियल इस्टेट, ऑफ आरे रोड, नीयर प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, गेट नं. 2, गोरेगांव पूर्व, मुंबई 400 063 से छपवाकर, रूम नं. ३६१, जाकिर अली चॉल, स्कॉटर कॉलोनी, जोगेश्वरी (पूर्व),मुंबई ४०० ०६० से प्रकाशित. संपादक - मोहम्मद सईद अकबर अली शेख मो.: ९९३००२६९४२ / ९९३००२६९४३
कार्यकारी संपादक - विक्रम सेन email -fightagainstcriminal2016@gmail.com RNI. No. : MAHHIN/2016/71734 सभी पद अवैतनिक है, (विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मुंबई होगा)